

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): (a) Yes, Sir. The notified prices are based on the estimated cost of production.

(b) The estimated calculated costs are nearly the same as the prices notified on 6th August, 1965. A copy of the notification is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-4844/65].

(c) The Tariff Commission Cost Schedules do not separately provide for profit margins. These Schedules provide for a 12 per cent return on capital employed and the same is included in the notified prices.

महाराष्ट्र राज्य को आयातित गेहूँ का संभरण

* 617. { श्री बे० शि० पाटिल :
श्री शिवाजीराव शं० वेष्टामुल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उस राज्य को आयातित गेहूँ का संभरण तत्काल बढ़ाने की मांग की है ताकि वे जाड़ों में वर्षा न होने के कारण इस वर्ष उत्पन्न हुमा खाद्य संकट दूर कर सके;

(ख) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र सरकार ने कितने गेहूँ की मांग की है; और

(ग) उस राज्य को अब तक कितना गेहूँ वस्तुतः भेजा जा चुका है और भेजे जाने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री बि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). इस वर्ष महाराष्ट्र में सर्दी की वर्षा के न होने से कोई खाद्य संकट पैदा नहीं हुआ था । महाराष्ट्र में इस वर्ष चार वर्षा वाले क्षेत्रों में से केवल एक क्षेत्र में वर्षा सामान्य से नीचे हुई थी । इस वर्ष महाराष्ट्र में खाद्यान्नों की कुल उपज भी गत वर्ष की अपेक्षा पर्याप्त अधिक हुई ।

महाराष्ट्र ने प्रति मास एक लाख मीट्रिक टन आयातित गेहूँ सप्लाय करने के लिये कहा था ।

(ग) जनवरी से अगस्त, 1965 की अवधि में महाराष्ट्र को 682.5 हजार मीट्रिक टन आयातित गेहूँ दी गयी है । आगामी सप्लाय उपलब्धि और महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों की कुल आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी ।

Famine in Rajasthan

* 618. **Shri Shiv Charan Mathur:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Rajasthan State is in the grip of acute famine due to the reported failure of Kharif crops in many districts;

(b) whether it is also a fact that the Chief Minister of the State has requested for a substantial help from the Central Government;

(c) if so, the details thereof; and

(d) Government's reaction thereto?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): (a) No such report has come from the State Government. However certain areas in the State have been declared as scarcity-affected areas.

(b) to (d). The Chief Minister of Rajasthan had requested for allotment of 10,000 tonnes of wheat for August, 1965 in addition to their quota of 5,000 tonnes, and, failing that, an allotment of 15,000 tonnes of wheat in September, 1965. For the month of September, 1965, a quota of 10,000 tonnes of wheat has been allotted to Rajasthan State from the Central Stocks. This is in addition to supply of about 1,000 tonnes of imported wheat per month to the roller flour mills in the State.

A loan of Rs. 90 lakhs was also sanctioned to the Government of Rajasthan on 12th April, 1965, towards the expenditure incurred on relief in

connection with scarcity during 1963-64 and 1964-65 (upto August 1965). This is part of the total financial assistance of Rs. 374.09 lakhs for meeting expenditure for the above purpose since 1963.

चीनी का उत्पादन

- *619. { श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० च० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसबा :
श्री बागड़ी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की तुलना में 31 जुलाई, 1965 तक चीनी के उत्पादन के राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जितना गन्ना पैदा होने की आशा है, उसे पेरने के लिये विभिन्न मिलों की गन्ना पेरने की कुल क्षमता पर्याप्त नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार में गन्ना काफी मात्रा में बिना पिरा रह जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार क्या योजना बना रही है ताकि 1965 में गन्ने की पूरी मात्रा की पिराई हो सके?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री वि० सुब्रह्मण्यम) : (क) प्रपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4845/65]।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। बालू सीजन में सारा उपलब्ध गन्ना पिरा जा चुका है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Demurrage on Foodgrains Ships

- *620. { श्री P. C. Borooah:
श्री P. R. Chakraverti:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large amount of demurrage had to be paid by Government for detaining the ships in Indian Ports which brought foodgrains from abroad during this year;

(b) if so, the total amount of demurrage paid during 1965 so far;

(c) the steps taken to minimise this loss; and

(d) the contemplated schemes for quickening the unloading process?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): (a) and (b). The amount of demurrage incurred on foodgrain ships, which arrived at all Indian ports from January, 1965 upto 31st July, 1965, is estimated at about Rs. 13.46 lakhs. Against this, despatch earned during the same period is estimated at about Rs. 24 lakhs. Thus the net despatch earned during the above period was about Rs. 10 lakhs.

(c) Following steps were taken to minimise the demurrage:—

1. Ships were diverted from one port to another to relieve congestion and to minimise demurrage.
2. To accelerate grain discharge from vessels and for more expeditious turn round of ships, a number of pneumatic discharging machines have been purchased and installed at Bombay and Kandla.
3. To improve grain clearance at major ports, the system of clearance through contractors has been abolished at Bombay, Madras and Vizag and